अपर्याप्त प्रतिक्रिया

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (भारतीय राजनीति) से संबंधित है।

द हिन्दू

05 जनवरी, 2022

ईडब्ल्यूएस की पहचान करने के लिए ₹8 लाख आय मानदंड को निर्धारित करने के पीछे के आधार को सरकार तार्किक ढंग से नहीं समझा पायी है।

सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा नियुक्त समिति द्वारा प्रस्तुत किया आधार विश्वास योग्य नहीं प्रतीत होता है कि ₹ 8 लाख की वार्षिक पारिवारिक आय एक सही मानदंड है। यह निर्धारित करने के लिए कि कोई आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से प्रवेश और नौकरियों में 10% आरक्षण प्राप्त करने के लिए योग्य है या नहीं।

सबमिशन ने इस धारणा को खारिज कर दिया कि सरकार ने "यांत्रिक रूप से" कट-ऑफ के रूप में ₹ 8 लाख को अपनाया था क्योंकि इसका उपयोग ओबीसी क्रीमी लेयर की पहचान के लिए किया गया था, यह कहते हुए कि आय मानदंड ओबीसी क्रीमी के लिए "अधिक कठोर" था। यह औचित्य, कुछ और मानदंडों के आधार पर, जो कुछ आय और व्यावसायिक मापदंडों को ओबीसी क्रीमी लेयर से बाहर करता है, हालांकि, आश्वस्त नहीं है क्योंकि कोर्ट का मुख्य प्रश्न अभी भी अनुत्तरित रह गया है।

कोर्ट ने कहा था कि ओबीसी वर्ग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है, और इसलिए उसे दूर करने के लिए अतिरिक्त बाधाएं थीं, और पूछा था कि क्या ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों श्रेणियों के लिए समान आय सीमा प्रदान करना मनमानी नहीं होगी? सरकार का हलफनामा इस प्रश्न का पर्याप्त उत्तर नहीं देता है। यह पूछे जाने पर कि क्या शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय शक्ति और राज्यों में प्रति व्यक्ति आय/जीडीपी में सभी अंतरों को इस संख्या पर पहुंचने पर विचार किया गया था, प्रस्तुतीकरण से पता चलता है कि यह अभ्यास संभव तो है लेकिन जटिल होगा। लेकिन यह कहते हुए कि ₹ 8 लाख की वार्षिक पारिवारिक आय मानदंड सही दृष्टिकोण है, समिति इसके आधार पर आबादी में ईडब्ल्यूएस व्यक्तियों की अनुमानित संख्या पर कोई डेटा प्रस्तुत नहीं करती है।

यदि उपलब्ध उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण जैसे 2011-12 एनएसएसओ रिपोर्ट, घरेलू उपभोक्ता व्यय के प्रमुख संकेतक आदि को आधार बनाये, तो आबादी का एक बड़ा हिस्सा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत "₹ 8 लाख से कम" कट-ऑफ के तहत आरक्षण के लिए पात्र होगा, जिससे सीमा तर्कहीन हो जाएगी। समिति का दावा है कि ₹ 8 लाख "प्रभावी आयकर छूट सीमा" से मेल खाता है, यहां तक कि करों का भुगतान करने से छूट प्राप्त एकमात्र आय स्लैब ₹ 2.5 लाख से कम आय वालों के लिए था, यह भी "आर्थिक रूप से कमजोर होने" के मानदंड को कम कड़े रूप में प्रस्तुत करता है।

सबमिशन इस तथ्य पर जोर देता है कि हाल ही में प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं (एनईईटी, यूपीएससी, जेईई) के परिणामों में विभिन्न आय वर्ग (0-₹ 2.5 लाख, ₹ 2.5-₹ 5 लाख, ₹ 5-₹ 8 लाख) में योग्य उम्मीदवारों का एक समूह दिखाया गया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं करता है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े ओबीसी की तुलना में भर्ती परीक्षाओं में अंक कट-ऑफ और भी कम क्यों थे। 103 वें संविधान संशोधन की वैधता, जिसके माध्यम से 2019 में ईडब्ल्यूएस कोटा पेश किया गया था, अभी भी संविधान पीठ के पास है। लेकिन शीर्ष अदालत को आरक्षण के लिए पात्र ईडब्ल्यूएस वर्गों की पहचान के लिए आय सीमा निर्धारित करने के लिए सरकारी समिति द्वारा अपनाए गए मानदंडों पर अधिक स्पष्टता की मांग करनी चाहिए।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. भारत में किस संविधान संशोधन के माध्यम से आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है?

(क) 101 वें

(ख) 102 वें

(ग) 103 वें

(घ) 110 वें

Expected Question (Prelims Exams)

Q. Through which constitutional amendment in India, reservation has been given on economic basis?

(a) 101st

(b) 102nd

(c) 103rd

(d) 110th

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. क्या आपके अनुसार भारत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को निर्धारित करने वाली आय सीमा उचित है? अपने मत के पक्ष में तर्क भी प्रस्तुत करें। (250 शब्द)

Q. Do you think the income limit determining the Economically Weaker Section (EWS) in India is appropriate? Give arguments in support of your opinion.

(250 Words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।